EDITORIAL

UNFAIR TREATMENT

It is not a fair deal with BSNL non-executive employees at the part of BSNL management well as at the part of the union government. The down trodden employees are unaware about the affordability, profitability and sustainability clause provisions in wage revision guideline issued by department of public enterprises.

The employees are mounting pressure upon the union that they are working for the nation even in abnormal situation like natural calamity disaster and keeping up the services of BSNL for the people of the nation and they also questioning that. The BSNL workers are implementing the government Telecom policy without applying their mind whether they are working for profit or for the loss. They know to work and serve the people with better services. It is a fact that the workers are not responsible for any financial loss of the company as they are contributing very sincerely to complete the task given to them at all times.

The DOT employees who opted to work in BSNL, now feeling cheated themselves by the government. As the government is deviating from its commitment which was made by them after an agreement signed the staff unions.

It is an unique situation in BSNL that more than 54% employees who opt to work in BSNL are facing stagnation. They are working for last 8/10 years without any increase of a single paisa in their salary. The NFTE BSNL held its national secretariat meeting on 23.01.2024 and after a long discussion it was decided to launch a trade union action as **"call attention cum protest week from 13.02.2024 to 17.02.2024".** The programme was absorbed in very intheistic manner throughout the nation.

Now, as assured by the management during our protest week from 13th February to 17th February, meeting of wage committee have been restarted. We honestly feel that we should use this opportunity to reach to the agreement for new pay scales which will remove stagnation and pave the way of considerable increase in basic pay of employees. In circle secretariat meeting held at New Delhi on 6th March, it was categorically told **by GS that management is ready to protect Pay Loss and also demand of no stagnation till 2007 will also be taken care of.** The maximum possible enhancement in NE-9 scale also can be considered.In view of this situation the circle secretaries meeting unanimously resolved to appeal to both the stalwarts of staff side in wage committee to sign the agreement at an earliest for emancipation of employees from the evil of stagnation and financial distress thereof. The circle secretaries are also hope that no other factor including fitment formula will become a hurdle in signing the agreement for new pay scales. However, if in future, executives get more fitment then non-executive will get the same and should be made applicable to them also. Hope our expectations do not turn into despair.

More over our NFTE has filed an appeal petition to our honourable Prime Minister which was well registered in PMO and sent to the DOT for further suitable action. It was a petition but the DOT officers could not took care upon it and replied to the PMO that due to affordability clause the BSNL workers are not eligible to get 3rd wage revision. This is a recorded reply of the DOT, our petition was request the honourable Prime Minister to arrange relaxation in affordability condition viewing the special condition of the BSNL as it is a strategic company to connect the nation within the policy frame of the Govt.

NFTE have appealed the PMO to review our petition in its real spirit and arrange relaxation in affordability condition.

In between it is clear stand of NFTE that we are ready to negotiate with the management to finalise the scales and the points raised by the NFTE well accepted by the management side.

We are hopeful that the negotiations will be completed before general elections. So that the agreed scales may be sent to DOT for approval.

NFTE ZINDABAD

संपादकीय

अनुचित बर्ताव

यह बीएसएनएल प्रबंधन के साथ–साथ केंद्र सरकार की ओर से बीएसएनएल के नान–एक्जीक्यूटिव कर्मचारियों के साथ उचित बर्ताव नहीं है। सार्वजनिक उद्यमों के रिपोर्ट विभाग द्वारा जारी वेतन संशोधन दिशानिर्देश में सामर्थ्य, लाभप्रदता और स्थिरता खंड प्रावधान के बारे में वंचित कर्मचारी अनभिज्ञ हैं।

कर्मचारी यूनियनों तथा कर्मचारियों पर दबाव है कि वे प्राकृतिक आपदा जैसी असामान्य स्थिति में भी देश के लिए काम करते रहें और देश के लोगों के लिए बीएसएनएल की सेवाएं जारी रखें। बीएसएनएल कर्मचारी सरकारी टेलीकॉम नीति को बिना अपना दिमाग लगाए लागू कर रहे हैं कि वे लाभ के लिए काम कर रहे हैं या घाटे के लिए। वे काम करना और बेहतर सेवाओं के साथ लोगों की सेवा करना जानते हैं, यह तथ्य है कि कर्मचारी कंपनी के किसी भी वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं क्योंकि वे उन्हें किए गए कार्य को पूरा करने में बहुत ईमानदारी से योगदान दे रहे हैं।

बीएसएनएल में काम करने का विकल्प चुनने वाले डीओटी कर्मचारी अब सरकार से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार कर्मचारी संघों के साथ हुए समझौते के बाद भी अपनी उस प्रतिबद्धता से भटक रही है।

बीएसएनएल में यह एक अनोखी स्थिति है कि बीएसएनएल में काम करने का विकल्प चुनने वाले 54% से अधिक कर्मचारियों को वेतन ठहराव का सामना करना पड़ रहा है।

पिछले 8/10 वर्षों से उनके वेतन में एक भी पैसे की वृद्धि नहीं हुई। एनएफटीई बीएसएनएल ने 23.1.2024 को अपनी राष्ट्रीय सचिवालय बैठक आयोजित की और लंबी चर्चा के बाद 13.2.2024 से 17.2.2024 तक **"ध्यान सह सुरक्षा सप्ताह"** के रूप में ट्रेड यूनियन कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से सम्पन्न हुआ।

अब, जैसा कि 13 फरवरी से 17 फरवरी तक हमारे विरोध सपताह के दौरान प्रबंधन ने आश्वासन दिया था, वेतन समिति की बैठक फिर से शुरू कर दी गई है। हम ईमानदारी से महसूस करते हैं कि हमें इस अवसर पर उपयोग नए वेतनमान के लिए समझौते पर करने के लिए करना चाहिए, जिससे गतिरोध दूर होगा और कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। 6 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित सीआई सचिवालय की बैठक में, हमारे जीएस द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रबंधन वेतन हानि की रक्षा के लिए तैयार हैं और 2027 तक कोई ठहराव नहीं होने की मांग पर भी ध्यान दिया जाएगा। इस स्थिति को देखते हुए एनई–9 स्केल में अधिकतम संभव वृद्धि पर भी विचार किया जा सकता है, हमने सर्वसम्मति से वेतन समिति में कर्मचारी पक्ष के दोनों दिग्गजों से कर्मचारियों को ठहराव की वित्तीय संकट की बुराई से मुक्ति के लिए समझौते पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की अपील करने का संकल्प लिया। हमें यह भी उम्मीद है कि फिटमेंट फार्मूला सहित कोई अन्य कारक वेतनमान के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने में बाधा नहीं बनेगा। हालांकि, यदि भविष्य में, कार्यकारी को अधिक उपयुक्तता मिलती है तो एक्जीक्युटिव का नॉन–एक्जीक्युटिव पर भी लागू किया जाना चाहिए, आशा है कि हमारी अपेक्षाएं निराशा में नहीं बदलेंगी।

इसके अलावा हमारे एनएफटीई ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को एक अपील याचिका दायर की है जिसे पीएमओ में अच्छी तरह से पंजीकृत किया गया था और आगे की उचित कार्रवाई के लिए डीओटी को भेजा गया था। यह एक याचिका थी लेकिन डीओटी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे सके और पीएमओ को जवाब दिया कि सामर्थ्य खंड के कारण बीएसएनएल कर्मचारी तीसरे वेतन संशोधन के लिए पात्र नहीं हैं। यह डीओटी का एक रिकार्डेड उत्तर है, हमारी याचिका में माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया था कि वे बीएसएनएल की विशेष स्थिति को देखते हुए सामर्थ्य की स्थिति में छूट की व्यवस्था करें क्योंकि यह सरकार की नीति के दायरे में देश को जोड़ने वाली एक रणनीतिक कंपनी है। हमने पीएमओ से हमारी याचिका की वास्तविक समीक्षा करने और सामर्थ्य की स्थिति में छूट की व्यवस्था करने की अपील की है।

इस बीच एनएफटीई का यह स्पष्ट रूख है कि हम वेतनमान को अंतिम रूप देने के लिए प्रबंधन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं और एनएफटीई द्वारा उठाए गए बिंदुओं को प्रबंधन पक्ष ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया है।

हमें उम्मीद है कि आम चुनाव से पहले बातचीत पूरी हो जायेगी ताकि सहमत वेतनमान को मंजूरी के लिए डीओटी को भेजा जा सके।

एनएफटीई जिन्दाबाद